बी.पी.डी.पी./आर.ई.ओ., रांची के मुख्य अभियंता

बनाम

मेसर्स स्कूट विल्सन कृपा ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

10 नवंबर, 2006

[अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 37(एल)(बी)-अपील स्पष्ट रूप से उस आदेश के खिलाफ है जो पुरस्कार को रद्द करता है या पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करता है-उच्च न्यायालय ने गलती से अन्यथा फैसला सुनाया-मध्यस्थता अधिनियम, 1940-धारा 39(एल)(vi)।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अपील को उसके गैर-स्थायी होने के आधार पर खारिज करने में गलती की है, क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के दायरे में नहीं आता है।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा:

इस मामले में सवाल यह है कि क्या अपील विचारणीय है। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया। अपील स्पष्ट रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37(1)(बी) के तहत विचारणीय है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय मामले से निपटेगा और अपील को विचारणीय मानते हुए गुण-दोष के आधार पर संबंधित पक्ष की जांच करेगा। (842-सी-डी)

भारत संघ बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2001) 8 एससीसी 470; गोवा राज्य बनाम वेस्टर्न बिल्डर्स, (2006) 6 एससीसी 239; धर्म प्रतिष्ठानम बनाम मधोक कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2005) 9 एससीसी 686; एस्सार कंस्ट्रक्शन बनाम एन.पी. राम कृष्ण रेड्डी,

(2000) 6 एससीसी 94; भारत संघ और अन्य बनाम मैनेजर मिस जैन एंड एसोसिएट्स, (2001) 3 एससीसी 277 और फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम कस्टोडियन, (2004) द्वितीय एससीसी 472, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4759, 2006।

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के मध्यस्थता अपील संख्या 2/2005 के दिनांक 4/6.4.2005 के निर्णय एवं अंतिम आदेश से। अपीलकर्ता की ओर से पिंकी आनंद एवं विश्वजीत सिंह

प्रतिवादी की ओर से डॉ. राजीव धवन, विवेक सिंह और लक्ष्मी रमन सिंह।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

अरिजीत पसायत, जे. अनुमति प्रदान की गई।

इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 37 के दायरे में नहीं आती है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 37(1)(बी) के अंतर्गत सुनवाई योग्य है। इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला इस न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2001] 8 एससीसी 470 और स्टेट ऑफ गोवा बनाम वेस्टर्न बिल्डर्स, (2006]** 6 सेक 239) में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है, और उच्च न्यायालय द्वारा यह माना जाना न्यायोचित था कि अपील स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ ऐसे पहलू जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए आधारों में विशेष रूप से नहीं उठाया गया है, लेकिन तर्कों के दौरान प्रस्तुत किया गया है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 37(I)(b) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 'पुराना अधिनियम') की धारा 39(I)(vi) के समरूप है। अधिनियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं:

"1996 अधिनियम:

धारा 37(I)(b) "आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल आदेशों से अपील सुनने के लिए विधि द्वारा अधिकृत न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों से अपील की जाएगी, अर्थात्:-

b. अधिनियम की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना"।

1940 अधिनियम:

धारा 39. अपील योग्य आदेश: "(I) इस अधिनियम के तहत पारित निम्नलिखित आदेशों से (और किसी अन्य से नहीं) एक अपील न्यायालय के मूल आदेशों से अपील सुनने के लिए विधि द्वारा अधिकृत न्यायालय में होगी:-

एक आदेश:

xxx xxx xxx xxx

(vi) एक पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना"।

धर्म प्रतिष्ठानम बनाम मधोक कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, [2005] 9 धारा 686 में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप से माना गया है:

> "27 मध्यस्थ की नियुक्ति और विवादों का संदर्भ उसके पास पूर्णतया अक्षम या अमान्य होने के कारण शून्य होने की स्थिति में, पुरस्कार शून्य होगा और अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के बावजूद, किसी भी उचित कार्यवाही में जब उसे लागू करने या उस पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। यह

निष्कर्ष न केवल ऊपर उल्लिखित निर्णीत मामलों से निकलता है, बल्कि कई अन्य मामलों से भी निकलता है, जिन्हें हम नोटिस करना चाहते हैं।

28. **छब्बा लाल बनाम कल्लू लाल और अन्य, एआईआर** (1946) पी.सी. 72 में उनके आधिपत्य ने माना है कि संदर्भ पर एक पुरस्कार एक वैध संदर्भ को पूर्वधारणा करता है। यदि कोई वैध संदर्भ नहीं है, तो कथित पुरस्कार शून्य है।

29. इस मुद्दे पर, देश के सभी उच्च न्यायालयों में लगभग एकमतता है। उदाहरण के लिए, हम कुछ मामलों का हवाला दे सकते हैं। **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अजीत मेहता एंड एसोसिएट्स, पुणे और अन्य**, एआईआर (1990) बॉम 45 में, खंडपीठ ने माना कि न्यायालय के पास धारा 30 के अंतर्गत आने वाले आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर पुरस्कार को रद्द करने का स्वप्रेरणा अधिकार है, जैसे कि मध्यस्थों द्वारा दिया गया पुरस्कार, जिन्हें धारा 8 के तहत कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पुरस्कार निस्संदेह शुरू से ही शून्य और अनिर्धारित होगा। **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम साउथ ईस्टर्न रेलवे, एआईआर** (1992) एम.पी. 47 और **राजेंद्र दयाल बनाम गोविंद** (1970) एमपीएलजे 322, दोनों खंडपीठ के निर्णयों में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि कुछ स्थितियों में न्यायालय धारा 30 के तहत आवेदन के बिना भी या धारा 30 के तहत याचिका दायर किए बिना भी निर्णय को रद्द कर सकता है, यदि न्यायालय पाता है कि निर्णय निरर्थक है या किसी पक्ष को ऐसा कार्य करने का निर्देश देता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है या स्पष्ट रूप से अवैध है। हमें इस बिंदु पर अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायिक राय का एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक सारांश एस.के. चावला द्वारा मध्यस्थता और सुलह के कानून - अभ्यास और प्रक्रिया (द्वितीय संस्करण, 2004 पृष्ठ 181-184) में निहित पाया जाता है, जिसका शीर्षक है - "क्या न्यायालय के पास मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने की स्वप्रेरणा शक्ति है -" और इसके तहत चर्चा में दिया गया उत्तर सकारात्मक है।

30. हालांकि **भारत संघ बनाम श्री ओम प्रकाश**, [1976] 4 धारा 32 में यह माना गया है कि किसी संदर्भ की अमान्यता के आधार पर आपत्ति धारा 30 के खंड (ए), (बी) और (सी) द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं की जाती है, फिर भी इसे अवशिष्ट अभिव्यक्ति "या अन्यथा अमान्य" में शामिल किया गया है और इस तरह के आवेदन किए जाने पर इसे अलग रखा जा सकता था। हालांकि, उपरोक्त निर्णय को यह मानने के लिए एक प्राधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक पुरस्कार जो शुरू से ही शून्य है और इसलिए एक अमान्य नियुक्ति और अधिनियम की धारा 8, 9 और 20 में निहित प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में एक अमान्य संदर्भ के परिणामस्वरूप अमान्य है, तब भी वैध माना जा सकता है यदि सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 30 के तहत आपत्ति के माध्यम से आपत्ति नहीं की जाती है।

31. पक्षों के बीच और फिर न्यायालय के समक्ष तीन प्रकार की स्थितियाँ उभर सकती हैं। सबसे पहले, एक मध्यस्थता समझौता, इसकी प्रवर्तनीयता के दृष्टिकोण से जांच के अधीन, एक हो सकता है, जो यदि कोई पक्षकार स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा का प्रयोग करके अपने विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का इरादा व्यक्त करता है, तो पक्षकारों और न्यायालय के पास अनुबंध को बाध्यकारी मानने और उसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अथवा, ऐसा कोई करार हो सकता है जो अस्पष्टता या अनिश्चितता से ग्रस्त हो, जिसकी व्याख्या, मध्यस्थता अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ में भी, पक्षकारों के इरादे को निश्चितता के साथ निकाले बिना नहीं की जा सकती, तो यह माना जाएगा कि कानून की दृष्टि में पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं था और मध्यस्थ नियुक्त करने या धारा 8, 9 और 20 के संदर्भ में विवादों का संदर्भ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे, यदि कोई मध्यस्थ या मध्यस्थ नामित हो सकते हैं, या कोई प्राधिकारी नामित हो सकता है जो मध्यस्थ नियुक्त करेगा, तो पक्षकारों को उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की वास्तविक पहचान के बारे में पहले ही बता दिया गया है; सहमति पहले ही स्पष्ट कर दी गई है और वह पक्षकारों और न्यायालय को बाध्य करती है। इस उद्देश्य के लिए कोई अवसर आने पर जो कुछ

किया जाना बाकी रह जाता है, वह है न्यायालय में समझौता दाखिल करना और पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भित करने का आदेश प्राप्त करना। तीसरा, यदि मध्यस्थ का नाम नहीं दिया गया है और मध्यस्थ को नियुक्त करने वाला प्राधिकारी भी निर्दिष्ट नहीं है, तो नियुक्ति और संदर्भ एकमात्र मध्यस्थ को दिया जाएगा, जब तक कि कोई अलग इरादा स्पष्ट रूप से न बताया गया हो। नियुक्ति और संदर्भ - दोनों पक्षों की सहमति से होंगे। जहां पक्ष सहमत नहीं होते हैं, वहां न्यायालय हस्तक्षेप करता है और नियुक्ति करने, संदर्भ देने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है, बशर्ते कि उस संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाए। हम यह जोड़ना चाहते हैं कि किसी पक्ष द्वारा कार्रवाई करने के लिए कहे जाने पर मात्र निष्क्रियता से निहित सहमति या स्वीकृति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति में शामिल होने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया न देना सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है और प्रतिवादी के लिए एकमात्र विकल्प मध्यस्थ की नियुक्ति और विवादों को उसके पास भेजने के आदेश के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना था। यह न्यायालय ही है जो अपीलकर्ता को कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य कर सकता था।"

एस्सार कंस्ट्रक्शन बनाम एन.पी. राम कृष्ण रेड्डी, [2000] 6 एस.सी.सी. 94 में की गई कुछ टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां यह माना गया था कि सीमा के आधार पर आपत्तियों को खारिज करने के खिलाफ अपील स्वीकार्य है। **यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैनेजर, मिस जैन एंड एसोसिएट्स,** [2001] 3 एस.सी.सी. 277 में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे। पैरा 11, 12 और 19 इस प्रकार हैं:

"11. उपर्युक्त धाराओं के मद्देनजर, यह कहा जा सकता है कि-

(क) किसी पुरस्कार की प्राप्ति के बाद, न्यायालय स्वप्रेरणा से न्यायालय के पुरस्कार नियम बनाने से इस आधार पर इंकार कर सकता है कि (i) पुरस्कार का कुछ भाग ऐसे मामले पर है जो मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया है; और (ii) पुरस्कार का रूप

अपूर्ण है या उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है। न्यायालय पुरस्कार को मध्यस्थ को वापस भी भेज सकता है यदि (i) जहां पुरस्कार ने मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है; या (ii) जहां उसने मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी मामले को निर्धारित किया है; या (iii) पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि उसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है; या (iv) यह पहली नजर में अवैध है। यह धारा 17 के कोष्ठक खंड के तहत भी प्रदान किया गया है जो प्रदान करता है "जहां न्यायालय पुरस्कार या पुनर्विचार के लिए मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले को वापस भेजने या पुरस्कार को अलग करने का कोई कारण नहीं देखता है, न्यायालय ... निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़ेगा।" इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यदि धारा 30 या 33 के तहत आपत्तियां दायर नहीं की जाती हैं, तो न्यायालय पुरस्कार के अनुसार डिक्री पारित करने के लिए बाध्य है।

(ख) सीमा अधिनियम की धारा 5 न्यायालय को धारा 30 या 33 के तहत आवेदन दायर करने के लिए समय बढ़ाने का विवेकाधिकार देती है, जिसमें पुरस्कार पर आपत्तियां उठाई जाती हैं।

(ग) आदेश IX नियम 13 सहित सिविल प्रक्रिया संहिता, डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष पुरस्कार प्रस्तुत करके शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होती है।

(घ) धारा 15 के तहत पुरस्कार को संशोधित करने या धारा 16 के तहत पुनर्विचार के लिए मध्यस्थ को पुरस्कार वापस भेजने की न्यायालय की शक्ति धारा 30 के तहत पुरस्कार को रद्द करने या धारा 33 के तहत मध्यस्थता समझौते या पुरस्कार की वैधता निर्धारित करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भिन्न होती है।

12. नतीजा यह है कि फैसला सुनाने से पहले न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या पुरस्कार को संशोधित करने या माफ करने का कोई कारण है। इसके अलावा 'निर्णय सुनाना' वाक्यांश अपने आप में तर्कसंगत आदेश द्वारा न्यायिक निर्धारण को इंगित करेगा ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके

कि पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री पारित की जाए। वेबस्टर के व्यापक शब्दकोश [अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, खंड 1 (1984)] में "निर्णय" शब्द को दिए गए अर्थों में से एक इस प्रकार है: "निर्णय का परिणाम; विचार-विमर्श या विचार-विमर्श के बाद लिया गया निर्णय या निष्कर्ष"। इसके अलावा, आदेश XX नियम 4(2) सी.पी.सी. के अनुसार 'निर्णय' में मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए। यह गैर-बोलने वाले आदेश की घोषणा के विपरीत है।

19. इसके अलावा, इस अपील में शामिल विवाद का बड़ा हिस्सा इस न्यायालय द्वारा **एस्सार कंस्ट्रक्शन बनाम एन.पी. राम कृष्ण रेड्डी**, [2000] 6 एससीसी 94 में दिए गए निर्णय द्वारा कवर किया गया है। न्यायालय ने देखा कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की प्रयोज्यता के कारण, यदि न्यायालय ने किसी भी कारण से निर्णय नहीं सुनाया है, यद्यपि आवेदन करने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है और देरी की क्षमा के लिए प्रार्थना के साथ पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है, तो न्यायालय तब तक निर्णय नहीं सुना सकता जब तक कि आवेदन खारिज नहीं हो जाता। न्यायालय ने यह भी देखा कि धारा 17 के तहत डिक्री पारित होने के बाद भी, धारा 30 के तहत आवेदन पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते पर्याप्त कारण स्थापित हो। किसी भी मामले में, आवेदन की अस्वीकृति पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करना होगा। यदि ऐसा आवेदन इस आधार पर खारिज किया जाता है कि इसमें देरी हुई है और सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई पर्याप्त कारण नहीं बनाया गया है, तो यह अधिनियम की धारा 39(1)(vi) के तहत एक अपील योग्य आदेश होगा।

पॉपुलर कंस्ट्रक्शन के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में इस मामले के विशिष्ट मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। उस निर्णय में यह माना गया कि "पर्याप्त कारण मामलों" के संबंध में अधिनियम की धारा 34(3) के प्रावधान जो विलम्ब की क्षमा से संबंधित विशेष प्रावधान हैं, सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'सीमा अधिनियम') की धारा 5 के सामान्य प्रावधानों को

ओवरराइड करते हैं। **वेस्टर्न बिल्डर्स मामले (सुप्रा) और फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम कस्टोडियन,** [2004) 11 एससीसी 472 में भी स्थिति को दोहराया गया था। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि विलम्ब की क्षमा के लिए प्रावधान करने वाली सीमा अधिनियम की धारा 5 को अधिनियम की धारा 34(3) द्वारा बाहर रखा गया है।

लेकिन वर्तमान मामले में प्रश्न सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता के बारे में नहीं है, और वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या अपील स्वीकार्य थी। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया। अपील स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय मामले पर विचार करेगा और अपील को सुनवाई योग्य मानते हुए गुण-दोष के आधार पर संबंधित पक्ष की जांच करेगा।

तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

डी.जी. **अपील का निपटारा किया जाता है।**

यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।